

रांची में, मंगलवार दिनांक 20 फरवरी, 2018 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कल्याण विभाग

1. अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग अध्यादेश-2018. स्वीकृत।

विधि विभाग

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा-14(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत 04 विशेष न्यायालय के गठन के संबंध में। स्वीकृत।

योजना-सह-वित्त विभाग  
(वित्त प्रभाग)

3. राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरोक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से महुँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। स्वीकृत।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

4. राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं 500 शैय्या वाले सरकारी अस्पतालों में अमृत दीनदयाल प्रधानमंत्री जनऔषधि स्टोर का अधिष्ठापन करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए एवं नियम-245 के अन्तर्गत एच०एल०एल० लाईफ केयर लिमिटेड (भारत सरकार के उद्यम) के मनोनयन के संबंध में। स्वीकृत।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

5. श्री कृष्ण कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, बलात्कार मामलों के लिये त्वरित न्यायालय, देवघर को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74 (ख) (ii) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्वीकृति। स्वीकृत।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

6. विशेष शाखा, झारखण्ड, रांची के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्पेशल इटेलीजेंस ब्यूरो (एस०आई०बी०) के गठन के संबंध में। **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

7. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) अन्तर्गत जलछाजन परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं सुदृढीकरण के लिए रु० 202.059 करोड़ की केन्द्र प्रायोजित विश्व बैंक संपोषित नीरांचल राष्ट्रीय जलछाजन परियोजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(कृषि प्रभाग)

8. राज्य योजनान्तर्गत 1864 पंचायत के लिये मृदा परीक्षक (मिनी लैब) की स्थापना हेतु नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया लि० (एन०ए०एफ०ई०डी०) के मनोनयन के संबंध में। **स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(कृषि प्रभाग)

9. राज्य योजनान्तर्गत मृदा परीक्षक (मिनी लैब) के 2600 रिफिल के क्रय हेतु नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया लि० (एन०ए०एफ०ई०डी०) के मनोनयन के संबंध में। **स्वीकृत।**

विधि विभाग

10. झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची में उनके प्रशासनिक स्थापना के सुचारु संचालन हेतु 60 (साठ) अराजपत्रित पदों के सृजन के संबंध में। **स्वीकृत।**

**कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग**  
**(कृषि प्रभाग)**

11. रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय के अधीन विस्तारित केन्द्र रामकृष्ण मिशन, मोराबादी, रांची, झारखण्ड को वार्षिक व्यय रु0 294.00 लाख (दो करोड़ चौरानबे लाख) मात्र का अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

**उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग**  
**(उच्च शिक्षा निदेशालय)**

12. Draft Statute Relating to admission and exclusion of colleges other than those managed and maintained by the University. **स्वीकृत।**

**कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग**  
**(कृषि प्रभाग)**

13. राज्य में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से देवघर एवं साहेबगंज जिलों में नई डेयरियों की स्थापना के लिए झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 261 (b) एवं नियम 332 को शिथिल करते हुए झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के पी०एल० खाता में संचित रु0 1322.40 लाख को झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के चालू बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति तथा उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत राशि भविष्य में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के चालू बैंक खाता में उपलब्ध कराने की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

**वाणिज्य-कर विभाग**

14. राज्य में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (GST) के क्रियान्वयन में M/S Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd को वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के आलोक में मनोनयन के आधार पर एक वर्ष के लिए Consultancy Service प्राप्त करने हेतु चयनित संस्था को वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के क्रियान्वयन के पश्चात के कार्यों हेतु एक वर्ष के लिए अवधि विस्तार करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

15. सरकारी एवं खासमहाल भूमि की लीज बंदोबस्ती/ नवीकरण की नीति में समरूपता लाने व सरकारी भूमि पर अवैध दखल-कब्जा की अवधि की गणना हेतु समरूप तिथि निर्धारण एवं तत्संबंधी अन्यान्य विषयों पर नीति निर्धारण के संबंध में। **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

16. झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2017 के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के प्रावधानों में संशोधन के संबंध में। **स्वीकृत।**

ह0/—  
(राजबाला वर्मा)  
मुख्य सचिव,  
झारखण्ड